GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

**RAJYA SABHA**
**STARRED QUESTION NO: 55***
TO BE ANSWERED ON: 21.07.2022

**Steps to reduce Deforestation**

55. SHRI S. SELVAGANABATHY:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has taken note of the fact that India has lost millions of hectares of tree cover over the last two decades; and
(b) if so, the preventive steps that have been taken/proposed to be taken by Government to reduce deforestation?

**ANSWER**

**MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BHUPENDER YADAV)**

(a) & (b) The statement is laid on the table of the House.

***

**Statement refer to in reply to part (a) to (b) of Rajya Sabha Starred Question No. 55 due for reply on 21.07.2022 regarding 'Steps to reduce Deforestation' by Shri S. Selvaganabathy**

(a) Forest Survey of India (FSI), Dehradun, an organization under the Ministry carries out the assessment of forest cover of the country biennially since 1987 and the findings are published in India State of Forest Report (ISFR). The forest cover assessment is a wall-to-wall mapping exercise based on remote sensing supported by intensive ground verification and field data from National Forest Inventory. ISFR 2021 is the latest report released by the Ministry on 13th January, 2022. As per ISFR 2021, the total forest cover of the country has increased by 38,251 square kilometre, tree cover has increased by 14,276 square kilometre and total forest and tree cover has increased by 52,527 square kilometre in the last two decades (ISFR 2001 to ISFR 2021). The details of forest and tree cover of the country in last two decades (ISFR 2001 to ISFR 2021) and change in forest and tree cover are given in the table below:-

**(Area in square kilometres)**

| Class | ISFR 2001 (a) | ISFR 2021 (b) | Change (b-a) |
|---|---|---|---|
| Forest Cover | 6,75,538 | 7,13,789 | 38,251 |
| Tree Cover | 81,472 | 95,748 | 14,276 |
| Forest and Tree Cover Combined | 7,57,010 | 8,09,537 | 52,527 |

(b) To compensate the problem of deforestation and to improve and increase the forest & tree cover in the country, afforestation programmes are taken up under various Centrally Sponsored Schemes of the ministry such as National Afforestation Programme (NAP) and National Mission for a Green India (GIM). Now NAP scheme has been merged with Green India Mission. The Ministry also supports school nursery and urban forestry programmes through people's participation. Afforestation activities are also taken up under various programmes /funding sources such as Compensatory Afforestation Funds under Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), afforestation activities under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA), National Agro-forestry Policy and Sub-mission on Agro-forestry (SMAF), National Bamboo Mission and National Mission for Sustainable Agriculture. In addition to above, State and UT Governments have their own afforestation and reforestation programmes. Almost every State has activities under social forestry, which largely focuses on tree planting in the areas outside forests. In addition, plantations are also done by various departments, Non-Government Organizations, Civil Society, Corporate bodies etc.

The multi departmental efforts have yielded good results in conserving environment by addressing the problem of deforestation, besides keeping the pace of development, which is evident from the fact that the forest cover has stabilized and has been constantly increasing over the years. As per the latest ISFR 2021, the total forest cover of the country has increased by 12,294 square kilometres in the last seven years (ISFR 2015 to ISFR 2021).

The details of forest cover of the country in the last seven years (ISFR 2015 to ISFR 2021) and change in forest cover with respect to previous assessments are given in the table below:-

**(Area in square kilometres)**

| ISFR Years | Total Forest Cover | Changes in forest cover w.r.t. previous ISFR | Change in percentage |
|---|---|---|---|
| ISFR 2015 | 7,01,495 | - | - |
| ISFR 2017 | 7,08,273 | 6,778 | 0.21 |
| ISFR 2019 | 7,12,249 | 3,976 | 0.56 |
| ISFR 2021 | 7,13,789 | 1,540 | 0.22 |

*****

**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *55**

**21.07.2022 को उत्तर के लिए**

**निर्वनीकरण को कम करने हेतु कदम**

***55. श्री एस. सेल्वागनबेथी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि गत दो दशकों में भारत कई मिलियन हेक्टेयर वन आच्छादित क्षेत्र खो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्वनीकरण को कम करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री भूपेन्द्र यादव)**

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**'निर्वनीकरण को कम करने हेतु कदम' के संबंध में श्री एस. सेल्वागनबेथी, द्वारा दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *55 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, द्वारा वर्ष 1987 से दो वर्षों के अंतराल पर देश के वनावरण का आकलन किया जाता है और उसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसफएसआर) में प्रकाशित किया जाता है। वनावरण का आकलन गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्र डाटा द्वारा समर्थित रिमोट सेंसिग पर आधारित एक भिति-दर-भिति (वॉल-टू-वॉल) मानचित्रण कार्य है। आईएसएफआर-2021 नवीनतम रिपोर्ट है जिसे मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2022 को जारी किया गया। आईएसएफआर-2021 के अनुसार, गत दो दशकों (आईएसएफआर-2001 से आईएसएफआर-2021) में देश के कुल वनावरण में 38,251 वर्ग किमी, वृक्षावरण में 14,276 वर्ग किमी और कुल वन तथा वृक्षावरण में 52,527 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। गत दो दशकों (आईएसएफआर-2001 से आईएसएफआर-2021) में देश के वन और वृक्षावरण तथा वन और वृक्षावरण में हुए परिवर्तन का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

**(वर्ग किमी में क्षेत्रफल)**

| श्रेणी | आईएसएफआर 2001(क) | आईएसएफआर 2001(ख) | परिवर्तन (ख-क) |
|---|---|---|---|
| वनावरण | 6,75,538 | 7,13,789 | 38,251 |
| वृक्षावरण | 81,472 | 95,748 | 14,276 |
| संयुक्त रूप से वन और वृक्षावरण | 7,57,010 | 8,09,537 | 52,527 |

(ख): देश में निर्वनीकरण की क्षतिपूर्ति करने तथा वन और वृक्षावरण में सुधार और वृद्धि करने हेतु, मंत्रालय की विभिन्न केंद्र-प्रायोजित स्कीमों जैसे- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत वनीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। अब एनएपी स्कीम को हरित भारत मिशन में विलय कर दिया गया है। मंत्रालय द्वारा लोगों की भागीदारी के माध्यम से स्कूल नर्सरी और शहरी वानिकी कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान किया जाता है। वनीकरण कार्यकलापों को विभिन्न कार्यक्रमों/निधीयन स्रोतों के तहत भी शुरू किया जाता है, जैसे- प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति और कृषि-वानिकी संबंधी उपमिशन (एसएमएएफ), राष्ट्रीय बांस मिशन तथा राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत वनीकरण कार्यकलाप। उपर्युक्त के अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अपने वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में सामाजिक वानिकी के तहत कार्यकलाप संचालित हैं, जिनमें अधिकांशत: वनों के बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, कार्पोरेट निकायों आदि द्वारा भी वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं।

अनेक विभागों द्वारा विकास की गति को बनाए रखने के अलावा निर्वनीकरण की समस्या का समाधान करके पर्यावरण के संरक्षण में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वनावरण स्थिर हो गया है और पिछले कुछ वर्षों से उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। नवीनतम आईएसएफआर-2021 के अनुसार, गत सात वर्षों (आईएसएफआर-2015 से आईएसएफआर-2021) में देश के कुल वनावरण में 12,294 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

गत सात वर्षों (आईएसएफआर-2015 से आईएसएफआर-2021) में देश के कुल वनावरण तथा पिछले आकलनों की तुलना में वनावरण में परिवर्तन का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

**(वर्ग किमी में क्षेत्रफल)**

| **आईएसएफआर वर्ष** | **कुल वनावरण** | **पिछले आईएसएफआर की तुलना में वनावरण में परिवर्तन** | **परिवर्तन की प्रतिशतता** |
|---|---|---|---|
| आईएसएफआर 2015 | 7,01,495 | - | - |
| आईएसएफआर 2017 | 7,08,273 | 6,778 | 0.21 |
| आईएसएफआर 2019 | 7,12,249 | 3,976 | 0.56 |
| आईएसएफआर 2021 | 7,13,789 | 1,540 | 0.22 |

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S. Selvaganabathy, put your first supplementary. क्वेश्चन्स-आंसर्स के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)..

SHRI S. SELVAGANABATHY: Sir, as part of the the National Forest Policy, 1988, India plans to bring 33 percentage under forest cover area. Under this, I would like to know what measures are being taken by the Ministry. ...*(Interruptions)*..

**श्री भूपेन्द्र यादव** : माननीय उपसभापति जी, भारत ने जो 33 परसेंट फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने की बात कही है, उसके लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून के द्वारा लगातार एक सर्वे का आयोजन किया जाता है। ...(**व्यवधान**)... मैं यह बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ने 13 जनवरी, 2022 को अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। ...(**व्यवधान**)... उसने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके हिसाब से देश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, उसमें 38,251 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ...(**व्यवधान**)... ट्री कवर भी जो इन्क्रीज़ हुआ है, वह 14,276 स्क्वायर किलोमीटर इन्क्रीज़ हुआ है। ...(**व्यवधान**)... टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर जो इन्क्रीज़ हुए हैं, उनमें लास्ट टू डिकेड्स में, 2001 से लेकर 2021 के बीच में, 52,527 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. SELVAGANABATHY: Sir, I would like to know whether there is any plan to involve the youth in the afforestation programme of India and make them innovative in this manner. ...*(Interruptions)*...

**श्री भूपेन्द्र यादव** : माननीय उपसभापति महोदय, अफॉरेस्टेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, जिसमें युवाओं को भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है और हम लोग कर भी रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... देश में नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया प्रोग्राम चलता है और नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की जो स्कीम है, उसको ग्रीन इंडिया मिशन के साथ जोड़ दिया गया है। ...(**व्यवधान**)... इन सबमें कम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन से लेकर अफॉरेस्टेशन एक्टिविटी को मनरेगा के साथ जोड़ना, नेशनल एग्रो-फॉरेस्ट्री पॉलिसी को आगे बढ़ाना, नेशनल बम्बू मिशन को आगे बढ़ाना, नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, इनमें न केवल युवा, बल्कि उसके साथ ही साथ हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस, सिविल सोसायटी और कॉरपोरेट बॉडीज़, सबको इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल। ...(**व्यवधान**)...

**डा. राधा मोहन दास अग्रवाल** : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम हैं, उनमें हम गैर-फलदार वृक्षों को लगाते हैं, क्या

इसका कोई विशेष कारण है और यदि नहीं है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हम आगामी जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम करें, उनमें फलदार वृक्षों को लगाने की योजना बनाएँ? **...(व्यवधान)...**

**श्री भूपेन्द्र यादव** : माननीय उपसभापति महोदय, हमारे द्वारा जो अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलता है, हमारी प्राथमिकता इस बात पर रहती है कि जो हमारे नेटिव वृक्ष हैं, जो हमारी जलवायु के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से हैं, वे ज्यादा से ज्यादा लगाये जायें। **...(व्यवधान)...** माननीय सदस्य का जो सुझाव है, निश्चित रूप से फलदार वृक्ष भी लगने चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो नेटिव जलवायु है, उसके हिसाब से वृक्ष लगने चाहिए, जो हमारा डिपार्टमेंट प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। **...(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति** : प्रश्न संख्या 56. **...(व्यवधान)...**

**56. [The questioner was absent.]*